IJAER/Sep-Oct-2013/Volume-2/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

छ.ग. में कृषि उत्पादकता (कोरबा जिले के विशेष संदर्भ में)

Dr.Suraj Kumar Gobhil
Asstt.Professor(Economics)
Govt.E.V.P.G.College Korba Distt - Korba (C.G)

भारत का 26 वां राज्य छत्तीसगढ़ 01 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में नवीन आयामों की ओर अग्रसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,40,196 अरबरइह परजे प्रदेष की लगभग 80 प्रतिषत् जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। छत्तीसगढ़ का अंषीय विस्तार 17.46' उत्तरी अक्षांष से 24.5' उत्तरी अक्षांष तक ओर 80.1'5 पूर्वी देषांष से 84.20' पूर्वी देषांष तक 135191 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। लम्बाई पूर्व से पष्चिम तक 140 किलोमीटर तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 360 किलोमीटर तक फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में 10 वॉ राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से 17 वां तथा साक्षरता में 23 वॉ स्थान है।

धान के कटौरे के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ अंचल के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रदेष में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.39 प्रतिषत् क्षेत्र कृषि भूमि के अंतर्गत है, जिसमें 51.57 प्रतिषत भग में कृषि होती है। लगभग 63 प्रतिषत् कार्यषल जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की खेती व सर्वाधिक प्रजाति के धान उगाए जाने के कारण इस प्रदेष को धन का कटोरा कहा जाता है। छ.ग. में अपार जल सम्पदा है, किन्तु सिचाई सुविधाओं का विस्तार सीमित होने के कारण यहॉ की कृषि लगभग मानसून पर निर्मर है।

साम्राज्यवाद परस्त कृषि नीति अपनाकर पहले बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मषीनों, खादों व कीटनाषकों के बाजार पर अपना अधिकार जमाने दिया और अब वे न केवल बीजों, बल्कि अनाजों की उपज पर भी अपना अधिकार जमा रहें है। अब ''कार्पोरेट खेती'' व लाभ के लिये खेती के नाम पर विदेषी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बड़ी पैमाने पर जमीन देने हेतु किसानों को माध्य किया जा रहा है। फलतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी जल, जंगल व जमीन पर कब्जा कर रही है।

छत्तीसगढ़ में जहॉ खेती रोजगार के अधिकांष अवसर पैदा करती है, वहॉ कृषि भूमि पर स्थापित उद्योग सामाजिक दृष्टि से विनाषकारी है। छ.ग. अपने सस्ते श्रम का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वे किसानों को उनके जमीन से बेदखल कर उनके जीवन–यापन के साधनों से वंचित करने का उपाय अपना रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य का छोटा जिला कोरबा जो एक औद्योगिक जिला है। कोरबा में कृषि भूमि पर पॉवर संयत्रों का स्थापित होना है और लगभग 18 पावर संयत्र स्थापित किए जाने की सम्भावना हैं। प्रदूषण की मार झोल रही इस जिले में प्रदूषण का प्रभाव कृषि पर भी पड़ रही है। जिले में अपार जलराषि के बावजूद कृषिकों को सिंचाई–सुविधाएं नहीं मिलने पर भूमि बंजर एवं अनउपजाउ हो रही है। औद्योगिक जिला होने के कारण अधिकांष कृषि भूमि अद्योगों में चले जाने के कारण कृषि रकबे के सामने और भी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, जितनी जमीन कृषि के लिये बची है, वह सिंचाई से वंचित है। जिले में कृषकों को आधुनिक तकनीकी से खेती करने के लिये प्रषिक्षण येाजना भी ठप पड़ी है।

कोरबा जिले में कम जमीनों में फसल उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, दोहरी फसल लेने हेतु प्रोत्साहित करने सहित कृषि की वैज्ञानिक तरीके का प्रषिझा कार्यक्रम चलाने आदि कई योजनाएँ जो कृषि विभाग द्वारा रूचित नहीं लिए जाने से बंद पड़ी हुई हे। जिल के कोरबा विकास खण्ड के पहाड़ी क्षेत्राों के किसान ही देहरी फसल लेते हैं, वह भी अपने दम पर कृषि विभाग की योजनाओं का अगर सही ढंग से इन पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जाये तो इसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं, लेकिन विभाग ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में षिविर लगाने में रूचि नहीं लेता चिर्रा, गिरारी कोलगा, मदनपुर, इन क्षेत्रों में जलस्त्रोतों का नजदीक होना एवं ग्रामीणों के स्वप्रयास द्वारा पहाड़ी नालों की पानी को बांधकर नाली के माध्यम से खेतों तक लाना है।

कोरबा जिले में स्थापित पॉवर संयत्रों एवं कोयला खदानों का बुरा प्रभाव कृषि उत्पादकता पर पड़ा है। जिले में लगभग 17 कोल परियोजनाओं के साथ विद्युत संयत्रों में – वंदना, लैंको, धीरू, रैंकी, राज्य शासन की दो इकाईयॉ, एनटीपीसी की एक विषाल परियोजना स्टारलाईट एवं बीसीपीपी को एक–एक ईकाई स्थापित है। ग्राम छुरी जिले के अति उत्पादकता क्षेत्रों में एक था, किन्तु वदना पावर संयंत्र के स्थापित होने के कारण अधिकंष कृषक भूमिहीन हो गए, भूमि से बेदखल कृषकों को प्राप्त मुवाअजे राषि से दूसरे स्थानों पर कृषि भूमि नहीं मिलने के कारण डनके सामने रोजी–रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। जो कृषक कभी ठाट से अपने खेतों में काम करते थे, वे आज पॉवर संयंत्र में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। यही हॉल लैंको स्थापित पर सरगबुन्दियॉ–पताड़ी क्षेत्रों का है।

कोरबा जिले के घटते कृषि उत्पादकता के उत्तरदायी कारणें में – अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, वर्षा की अनिष्चितता, अज्ञान एवं गरीब कृषकों की प्रधनता, जोतो का छोटा आकार, पर्याप्त विपणन सुविधा न होना, कृषको की ऋृण ग्रस्तता, कृषि अनुसंधान का अभाव, नवीन तकनीकों का कम उपयोग, कृषि पर जनसंख्या का अति दबाव, भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डित होना, उन्नतबीज, खाद का कम उपयोग, दोषपूर्ण भू–धारण प्रणाली, कृषि प्रसार सेवा केन्द्रों की कमी, मंहगाई, फसलचक्र का अभाव, फसल बीमा योजना का सही ढ़ंग से क्रियान्ति न होना, भू–संरक्षण में कमी, बाढ़ एवं सूचनाा का प्रकोप, पौध संरक्षण का अभाव, मृदा परीक्षण का अभाव, श्रम की उत्पादकता में कमी, भूमि की उत्पादकता में कमी, कृषि विद्युतीकरण का अभाव प्रमुख हैं, किन्तु ज्वलंत कारण उपजाउ कृषि भूमि में उद्योगों का स्थापित होना है।

औद्याोगिक की बाढ़ में कोरबा जिले में कृषि व्यवसाय को गौंड़ बना दिया है। जिले में विद्युत संयत्रों की अधिकता के बावजूद न तो ग्रामीण कृषि का विद्युतीकरण हुआ और न ही लोगो को पर्याप्त रोजगार मिला, बल्कि मिला तो – प्रदूषण की मार एवं महंगी बिजली। गरीब कृषक के सामने जीवन–यापन की समस्या बेहद चिंतनीय है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कुंजी है। कोरबा जिले में भी उद्योगों के साथ–साथ कृषि के विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्रांतिकारी बदलाव लाने की आवष्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

01. योजना (मासिक पत्रिका) नवम्बर 2011 पृ. –08
02. शोध उपक्रम पृ. 08 वर्ष 12 अंक 22 अप्रैल 2006 छ.ग. शोध संस्थान, रायपुर (छ.ग.)
03. मिश्रा, जे.पी., अर्थषास्त्र, साहित्य भवन, आगरा,
04. दत्त, रूद एवं सुंदरम, के.पी.एम. '' भारतीय अर्थव्यवस्था'' एस. चांद कम्पनी लि. न्यू दिल्ली।
05. दैनिक नवभारत, 11 जनवरी 2012

डॉ. एस. के. गोभिल
सहायक प्राध्यापक (अर्थषास्त्र)
शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)